नवसर्जन संस्कृति

RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 101
दि. 09.08.2025,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : VINOD KUMARI Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

संक्षिप्त समाचार

दिल्ली विस ने स्कूल फीस विनियमन विधेयक को मंजूरी दी, जिससे अभिभावकों को फीस वृद्धि पर वीटो पावर मिल गई

दिल्ली विधानसभा ने स्कूल फीस विनियमन विधेयक, 2025 को मंजूरी दे

दी है, जिससे माता-पिता को फीस वृद्धि पर वीटो शक्ति मिल गई है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि स्कूल प्रबंधन एकतरफा फीस नहीं बढ़ा सकता। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि अगर एक भी माता-पिता असहमत होते हैं, तो फीस वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

पीएम मोदी के स्वागत के लिए चीन तैयार, ट्रंप से तनाव के बीच होगा दोस्ती का 'महा सम्मेलन'

(जीएनएस)।

चीन में होने वाली SCO समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित भागीदारी का शी जिनपिंग ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। यह सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन शहर में आयोजित होगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की।

'दोस्ती का सम्मेलन'

जियाकुन ने कहा, "चीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रउड तियानजिन समिट में भागीदारी के लिए स्वागत करता है। हमें विश्वास है कि सभी पक्षों के साझा प्रयासों से यह सम्मेलन एकजुटता, मित्रता और सार्थक परिणामों का प्रतीक बनेगा।" उन्होंने आगे कहा कि यह बैठक एससीओ को "एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी, जिसमें अधिक समन्वय, ऊर्जा और उत्पादकता देखने को मिलेगी।" चीन ने इस सम्मेलन को 'दोस्ती का सम्मेलन' बताया है।

यह संभावित यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब अमेरिका ने भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसकी चीन पहले ही कड़ी आलोचना कर चुका है। पीएम मोदी चीन यात्रा से पहले जापान भी जा सकते हैं, जहां वे जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ इस सालाना द्विपक्षीय सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं।

पहले भी दो बार मोदी जा चुके हैं चीन

प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा का एक इतिहास रहा है। इससे पहले वे 2018 में दो बार चीन का दौरा कर चुके हैं। पहली बार अप्रैल में उन्होंने वुहान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक अनौपचारिक शिखर वार्ता की थी। दूसरी बार, जून में किंगदाओ में एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे।

2019 में भारत आए थे जिनपिंग

इसके बाद 2019 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए थे, जहां दूसरी अनौपचारिक शिखर बैठक हुई थी। यह बैठक 2017 के डोकलाम गतिरोध के बाद द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य करने की एक महत्वपूर्ण कोशिश थी।

गलवान घाटी झड़प के बाद बदले थे समीकरण

हालांकि, 2020 में भारत-चीन संबंधों में भारी गिरावट आई, जब लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर झड़पें हुईं और गलवान घाटी में खूनी संघर्ष हुआ। जून 2020 की उस झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे।

'काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव' महान क्रान्तिकारियों के स्मरण का एक महान दिवस, यह वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा : मुख्यमंत्री

(जीएनएस)।

लखनऊ : आदित्यनाथ जी ने कहा कि आज काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का समापन कार्यक्रम है। आज से 100 वर्ष पहले 09 अगस्त, 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन के माध्यम से उस समय के महान क्रान्तिकारियों ने भारत की जनता के खून-पसीने की कमाई को इंग्लैंड ले जाने का कुत्सित प्रयास करने वाली ब्रिटिश हुकूमत के खजाने को अपने कब्जे में लेकर क्रान्तिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया था।

मुख्यमंत्री जी आज यहां काकोरी शहीद स्मारक, लखनऊ में 'काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के समापन समारोह एवं वीरों को नमन' कार्यक्रम के अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने काकोरी शहीद स्मारक में स्थित शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम

सेनानियों एवं शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री जी ने पुस्तक 'काकोरी ट्रेन एक्शन-साहस, बलिदान एवं आजादी की कहानी' का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी एवं सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा लगाई गयी काकोरी ट्रेन एक्शन पर आधारित चित्र एवं अभिलेख प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने शहीद स्मारक प्रांगण में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण किया। मुख्यमंत्री जी ने फोटो बूथ पर सेल्फी ली तथा बालिकाओं से राखी बंधवाई। समारोह में संस्कृति विभाग के तत्वावधान में 100 कलाकारों द्वारा 'काकोरी की अमर गाथा' नाट्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गयी। इस अवसर पर काकोरी ट्रेन एक्शन पर आधारित लघु फिल्म प्रदर्शित की गयी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस पूरे अभियान को नेतृत्व प्रदान करने वाले पं0 राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठा0 रोशन सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी सहित क्रान्तिकारियों की एक लम्बी श्रृंखला थी, जिन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने अलग-अलग जेलों में बन्द करके, बिना सुनवाई का अवसर दिये ही फांसी के फंदे पर पहुंचाने का काम किया था। पं0 राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। इसी प्रकार अन्य क्रान्तिकारियों को गोण्डा, फैजाबाद और नैनी जेल में फांसी दी गई। चन्द्रशेखर आजाद ब्रिटिश हुकूमत के हाथ नहीं पड़े, बल्कि उन्होंने मुकाबला करते हुए स्वयं वीरगति प्राप्त की। आज का यह शताब्दी महोत्सव उन महान क्रान्तिकारियों के स्मरण का एक महान दिवस है। यह वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा भी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि क्रान्तिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत के मात्र 4,600 रुपए के खजाने को अपने कब्जे में लिया था, जबकि इन क्रान्तिकारियों को पकड़ने और बिना सुनवाई उन्हें फांसी देने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 10 लाख रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की थी। आज से 100 वर्ष पहले देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले क्रान्तिकारियों का स्मरण करने और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हर भारतवासी को प्राणप्रण से जुटना चाहिए। आज का यह समारोह इसी संकल्प को आगे बढ़ाने वाला है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के दक्षिण जोन के लांभा वार्ड में अर्बन फॉरेस्ट पार्क का लोकार्पण किया

मुख्यमंत्री ने अर्बन फॉरेस्ट पार्क में लगाई गई भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा का अनावरण किया

गांधीनगर, 08 अगस्त : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को अहमदाबाद के दक्षिण जोन के लांभा वार्ड मंच सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के आधार पर विकसित किए गए अर्बन फॉरेस्ट पार्क का लोकार्पण किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया।

लांभा वार्ड में तैयार किया गया यह अर्बन फॉरेस्ट 4464 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। इस गार्डन को 55 लाख रुपए की लागत से विकसित किया गया है।

इस अर्बन फॉरेस्ट में मियावाकी पद्धति से साग, खेर, बांस, सीसम और अर्जुन जैसे लगभग 8000 देशी पेड़ लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, यहां 250 मीटर लंबाई का वॉक-वे भी तैयार किया गया है।

अर्बन फॉरेस्ट पार्क के लोकार्पण अवसर पर अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभा जैन, मनपा आयुक्त श्री बंछानिधी पाणि, शहर के विधायक, पार्षद और महानगर पालिका के पदाधिकारी मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में अहमदाबाद महानगर पालिका ने अहमदाबाद शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने के संकल्प को पूरा किया है

अब, क्लीन सिटी अहमदाबाद को ग्रीन सिटी बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए महानगर पालिका ने मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश में 40 लाख पेड़ लगाने के लिए मिशन फोर मिलियन ट्रीज 2025 अभियान शुरू किया है।

श्री मनोहर लाल खट्टर और डॉ. जितेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा मिशन पर चर्चा करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई

(जीएनएस)।

नई दिल्ली स्थित संसद भवन में आज विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा मिशन पर चर्चा के लिए संयुक्त रूप से एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भारत के स्वच्छ ऊर्जा बास्केट का विस्तार करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य और नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने को लेकर देश की प्रतिबद्धता को देखते हुए बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक के दौरान विभिन्न चालू और आगामी परियोजनाओं से 14 गीगावॉट की वृद्धि के माध्यम से भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावॉट से 2032 तक 22 गीगावॉट तक बढ़ाने के रोडमैप की विस्तार से समीक्षा की गई।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री,

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने परमाणु क्षेत्र को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोलने की सरकार की ऐतिहासिक पहल पर प्रकाश डाला और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) कार्यक्रम के प्रति उद्योगों की ओर से मिली मजबूत और जीवंत प्रतिक्रिया का भी उल्लेख किया। इसके परिणामस्वरूप व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई। अप्रैल में आयोजित चौथी सलाहकार समिति की बैठक के परिणामों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके, इसके लिए तेजी से काम किया गया।

विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रगति में तेजी लाने के लिए कई प्रमुख सुझावों की रूपरेखा तैयार की। इनमें नियामक मंजूरी को सुव्यवस्थित करना, प्रलेखन (दस्तावेजीकरण) को मानकीकृत करना, प्रसंस्करण समय सीमा को अनुकूलित करना, सामान्य प्रस्तावों पर जोर देना, लाइसेंसों को समन्वित करना और तकनीकी उन्नयन और क्षमता निर्माण में निवेश करना शामिल हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने निजी क्षेत्र के प्लेयर्स के बीच जागरूकता पैदा करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इनमें से कइयों ने निजी भागीदारी के लिए परमाणु क्षेत्र को खोले जाने पर प्रसन्नता जाहिर की।

विद्युत मंत्री ने समय-सीमा का पालन करने और स्थापित रोडमैप के अनुसार परियोजनाओं में तेजी लाने के महत्व पर बल दिया।

बैठक में परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग (एईसी) के अध्यक्ष डॉ. अजीत कुमार मोहंती, विद्युत मंत्रालय के सचिव श्री पंकज अग्रवाल, एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री गुरदीप सिंह, भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री भुवन चंद्र पाठक के अलावा विद्युत एवं अणु ऊर्जा विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

पीके की तीसरी किस्त ने उड़ाई एनडीए की नींद, सबूतों के साथ भाजपा के नेता-मंत्री को कटघरे में किया खड़ा

सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (पीके) ने एक बार फिर बिहार सरकार के बड़े मंत्री पर बड़ा हमला बोला है। पटना में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के तीसरे भाग में पीके ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और दिलीप जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

प्रशांत किशोर ने दावा किया कि दिलीप जायसवाल से रिश्वत लेकर फ्लैट खरीदने, एमजीएम मेडिकल कॉलेज को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने, और एम्बुलेंस खरीद में घोटाला हुआ है। पीके ने दस्तावेजी सबूतों के साथ भाजपा और इसके मंत्रियों को कठघरे में खड़ा किया।

सोशल मीडिया पर दोस्ती..फिर इमोशनल ब्लैकमेल, मुंबई में 80 साल के बुजुर्ग से ठगों ने उड़ाए 9 करोड़

मुंबई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें 80 वर्षीय बुजुर्ग को सोशल मीडिया के जरिये एक हाई-प्रोफाइल ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाया गया। वे

अब तक भारत में मांसाहारी दुग्ध उत्पाद और चारा बेचना चाहता है अमेरिका, दूध के बाजार को अमेरिका हड़पना चाहता है। जबकि वेंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वुछ माह पहले ही दस हजार नई वृषि सहकारी समितियों को हरी झंडी दिखाई है। अगले पांच साल में इनकी संख्या दो लाख तक पहुंचाने की है। इन्हीं सहकारी संस्थाओं के जरिए वृषि और दुग्ध उत्पादों को भारत से लेकर एशिया और यूरोप तक बाजार में पहुंचाने की है।

भारत सरकार ने अमेरिका से हथियारों की खरीद बंद कर दी? रॉयटर्स के दावे पर रक्षा मंत्रालय ने क्या कहा

(जीएनएस)।

भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते टैरिफ विवाद के बीच हथियार और विमान खरीद को लेकर नई हलचल मच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लगाने के बाद न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया था कि, भारत ने अमेरिका से रक्षा खरीद की अपनी योजना को रोक दिया है।

यह खबर ऐसे समय आई है, जब दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक मोर्चों पर तनाव लगातार बढ़ रहा है।हालांकि, रक्षा मंत्रालय ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है।

रक्षा मंत्रालय ने क्या कहा?

मंत्रालय का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा खरीद संबंधी वार्ता में कोई रुकावट नहीं आई है और विभिन्न परियोजनाएं तय प्रक्रिया के मुताबिक आगे बढ़ रही हैं। मंत्रालय ने रॉयटर्स की रिपोर्ट को 'झूठा और मनगढ़ंत' बताते हुए साफ किया कि टैरिफ विवाद का रक्षा खरीद पर कोई असर नहीं पड़ा है।

रॉयटर्स ने क्या कहा था?

रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत में असंतोष बढ़ा है। इस असंतोष के चलते केंद्र सरकार ने अमेरिका से नए हथियार और विमान खरीदने की योजना को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है।

खबर में कहा गया कि इस फैसले की जानकारी तीन भारतीय अधिकारियों ने दी, जो मामले से सीधे तौर पर जुड़े हैं। रॉयटर्स के मुताबिक, ट्रंप ने 6 अगस्त को भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर नाराजगी जताई थी और भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया था। इससे पहले ही लगाए गए 25 प्रतिशत टैरिफ को मिलाकर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया, जो किसी भी अमेरिकी व्यापारिक साझेदार के लिए सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ट्रंप ने भारत पर यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को आर्थिक मदद पहुंचाने का आरोप लगाया था।

टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच जारी है टकराव

तेजस्वी यादव को 16 अगस्त तक जमा करना होगा अपना ईपीआईसी, चुनाव आयोग ने क्यों दिया अल्टीमेटम?

(जीएनएस)।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी घमासान अपने चरम पर है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। पटना के निर्वाचन अधिकारी ने तेजस्वी को नोटिस भेजकर 16 अगस्त 2025 तक अपना वोटर आईडी जमा करने का अल्टीमेटम दिया है।

नोटिस में दावा किया गया है कि तेजस्वी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस EPIC नंबर को दिखाया, वह फर्जी हो सकता है। यह मामला बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया और वोटर लिस्ट विवाद के बीच और गमार्ता जा रहा है। आइए, जानते हैं इस सियासी ड्रामे की पूरी कहानी...

क्या है विवाद?

तेजस्वी यादव ने 2 अगस्त 2025 को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनसनीखेज दावा किया था कि उनका नाम बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से

हटा दिया गया है। उन्होंने EPIC नंबर RAB2916120 दिखाते हुए कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इसे सर्च करने पर 'No Records Found' का मैसेज आया। तेजस्वी ने इसे सियासी साजिश करार देते हुए आरोप लगाया कि उनके जैसे बड़े नेता का नाम अगर वोटर लिस्ट से हट सकता है, तो आम लोगों का क्या हाल होगा?

हालांकि, चुनाव आयोग ने तुरंत पलटवार करते हुए तेजस्वी के दावे को खारिज कर दिया। आयोग ने वोटर लिस्ट का वह पेज सार्वजनिक किया, जिसमें तेजस्वी का नाम EPIC नंबर RAB0456228 के साथ दीघा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 204 (बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पुस्तकालय भवन) में क्रमांक 416 पर दर्ज है। आयोग ने साफ किया कि तेजस्वी का नाम लिस्ट में मौजूद है और उनका दूसरा EPIC नंबर रिकॉर्ड में नहीं मिला।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

राजकोट मंडल में डबल ट्रैक कार्य के चलते कुछ और ट्रेनें होंगी प्रभावित

पश्चिम रेलवे के राजकोट मंडल में स्थित लाखाबावल-पीपली-कानालुस सेक्शन में डबल ट्रैक कार्य के चलते 20 अगस्त से लेकर 23 अगस्त, 2025 तक कुछ ट्रेनें प्रभावित होगी। प्रभावित होने वाली ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

आंशिक रूप से रद्द की गयी ट्रेनें:

1. 21.08.2025 को मुंबई सेंट्रल से रवाना होने वाली ट्रेन नं 22945 मुंबई सेंट्रल-ओखा सौराष्ट्र मेल को जामनगर में शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। इस तरह यह ट्रेन जामनगर-ओखा के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

2. 20.08.2025 को एरणाकुलम से रवाना होने वाली ट्रेन नं 16338 एरणाकुलम-ओखा एक्सप्रेस को हापा में शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। इस तरह यह ट्रेन हापा-ओखा के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

3. 22.08.2025 की ट्रेन नं 22946 ओखा-मुंबई सेंट्रल सौराष्ट्र मेल ओखा की जगह जामनगर से शुरू होगी। इस तरह यह ट्रेन ओखा-जामनगर के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

4. 23.08.2025 की ट्रेन नं 16337 ओखा-एरणाकुलम एक्सप्रेस ओखा की जगह हापा से शुरू होगी। इस तरह यह ट्रेन ओखा-हापा के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

रिशेड्यूल की गयी ट्रेनें:

1. ट्रेन नं 15635 ओखा-गुवाहाटी एक्सप्रेस 22.08.2025 को ओखा से अपने निर्धारित समय 12.15 बजे की जगह 5 घंटा और 45 मिनट की देरी से 18.00 बजे प्रस्थान करेगी।

2. ट्रेन नं 19269 पोरबंदर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 22.08.2025 को पोरबंदर से अपने निर्धारित समय 19.40 बजे की जगह 1 घंटा और 10 मिनट की देरी से 20.50 बजे प्रस्थान करेगी।

रेल यात्रियों से निवेदन है कि वे उपरोक्त फेरबदल को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा प्रारम्भ करें और ट्रेनों के परिचालन संबंधित नवीनतम अपडेटस की जानकारी के लिए www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन करें ताकि किसी प्रकार कि असुविधा ना हो।

अमित शाह एवं नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री,बिहार द्वारा सीतामढ़ी-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस के परिचालन का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ

अमित शाह,गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार एवं नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा दिनांक 08.08.2025 को सीतामढ़ी से नई दिल्ली के लिए एक नई अमृत भारत ट्रेन सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया । आज इसका परिचालन सीतामढ़ी से 05599 सीतामढ़ी-दिल्ली उद्घाटन स्पेशल के रूप में किया गया ।

दिल्ली और सीतामढ़ी के मध्य गाड़ी सं. 14048/14047 दिल्ली-सीतामढ़ी-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित परिचालन दिल्ली से 09.08.2025 से प्रत्येक शनिवार को तथा सीतामढ़ी से 10.08.2025 से प्रत्येक रविवार को किया जाएगा ।

गाड़ी सं. 14048 दिल्ली-सीतामढ़ी अमृत भारत एक्सप्रेस 09.08.2025 से प्रत्येक शनिवार को दिल्ली से 14.00 बजे खुलकर गाजियाबाद, टुंडला, कानपुर सेंट्रल,

लखनऊ, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, कप्तानगंज, सिसिवा बाजार, बगहा, नरकटियागंज, सिकटा, रक्सौल, बैरगनिया स्टेशनों पर रूकते हुए अगले दिन 10.45 बजे सीतामढ़ी पहुंचेगी । वापसी में गाड़ी सं. 14047 सीतामढ़ी-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस 10.08.2025 से प्रत्येक रविवार को सीतामढ़ी से 22.15 बजे खुलकर उपरोक्त स्टेशनों पर रूकते हुए अगले दिन 22.40 बजे दिल्ली पहुंचेगी ।

विदित हो भारतीय रेल की ओर से बिहार को मिलने वाली यह सातवीं अमृत भारत ट्रेन है। इससे पहले जब देश में पहली बार अमृत भारत ट्रेनें बनकर तैयार हुई थी, तो उनका परिचालन दरभंगा से वाया अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल तथा मालदा टाउन से सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरू के बीच किया गया था। सहरसा और मुंबई के मध्य अमृत भारत एक्सप्रेस के परिचालन का प्रारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था । इसके अलावा पटना और नई दिल्ली के बीच प्रतिदिन अमृत भारत एक्सप्रेस के साथ-साथ मोतिहारी से आनंद विहार के लिए, दरभंगा से लखनऊ तथा भागलपुर, गया, सासाराम के रास्ते मालदा टाउन से लखनऊ के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है जिससे बिहार के लोगों को काफी लाभ मिल रहा है।

अमृत भारत ट्रेनों का निर्माण मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री में किया गया है।

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने स्वच्छता अभियान के दौरान किया श्रमदान, पश्चिम रेलवे पर बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है 'स्वच्छता अभियान'

(पहली तस्वीर) पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर श्रमदान करते हुए। (दूसरी तस्वीर) श्री गुप्ता मुंबई सेंट्रल के मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज सिंह के साथ वृक्षारोपण अभियान में भाग लेते हुए।

पश्चिम रेलवे द्वारा श्रमदान और वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा

मुंबई,

भारतीय रेल द्वारा हमारे देश में मनाये जा रहे स्वतंत्रता दिवस समारोह के एक भाग के रूप में स्वच्छता एवं सार्वजनिक स्वच्छता के राष्ट्रीय उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए "स्वच्छता अभियान" मनाया जा रहा है। यह अभियान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सभी जोनों और उत्पादन इकाइयों में दो चरणों में अर्थात 1 से 15 अगस्त, 2025 तक और उसके बाद 16 अगस्त से 31 अक्टूबर, 2025 तक मनाया जा रहा है। यह अभियान रेलवे के सभी क्षेत्रों अर्थात स्टेशनों, ट्रेनों, कॉलोनियों, कार्यालयों, डिपो और कारखानों आदि में स्वच्छता के प्रति हमारे प्रयासों को दर्शाता है, साथ ही कर्मचारियों और यात्रियों के बीच स्वच्छता के प्रति जागरूकता को भी बढ़ावा देता है।

इसी भावना के साथ पश्चिम रेलवे भी अपने सभी मंडलों और इकाइयों में "स्वच्छता अभियान" का सक्रिय रूप से पालन कर रही है। इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने 8 अगस्त, 2025 को मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर श्रमदान में अग्रणी भूमिका निभाई और एक मिसाल कायम की। इस अवसर पर मुंबई सेंट्रल के मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज सिंह और अन्य वरिष्ठ रेलवे अधिकारी एवं कर्मचारी भी उनके साथ शामिल हुए। इस अवसर पर महाप्रबंधक ने अपने संबोधन में स्वच्छता बनाए रखने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी को रेलवे स्टेशनों और आसपास के क्षेत्रों के रखरखाव और सौंदर्यीकरण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद श्री गुप्ता ने वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, "स्वच्छता अभियान" "स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत" के दृष्टिकोण के अनुरूप सफाई, स्वच्छता, पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी और सामुदायिक सहभागिता पर जोर देता है। इस अभियान की शुरूआत महाप्रबंधक, प्रमुख विभागाध्यक्षों और क्षेत्रीय स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों, मंडल स्तर पर मंडल रेल प्रबंधकों और कारखाने स्तर पर मुख्य कारखाना प्रबंधकों द्वारा स्वच्छता शपथ दिलाकर की गई, जिसमें स्वच्छता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। श्री विनीत ने आगे बताया कि कर्मचारियों और जन-स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी से कई स्थानों पर नुक्कड़ नाटक, स्वच्छ रथ रैलियाँ और प्रभात फेरियाँ आयोजित की जा रही हैं। आम जनता को जोड़ने के लिए स्वच्छता थीम पर आधारित सेल्फी बूथ स्थापित किए गए हैं। कर्मचारियों और प्रभावशाली व्यक्तियों की भागीदारी से स्टेशनों, कार्यालयों और रेलवे कॉलोनियों में सघन स्वच्छता अभियान और श्रमदान आयोजित किए जा रहे हैं। स्वच्छता कार्यकताओं के लिए स्वास्थ्य जाँच शिविर लगाए जा रहे हैं। लोगों को स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्वच्छता हस्ताक्षर अभियान चलाए जा रहे हैं। कैटरिंग कर्मचारियों के लिए जागरूकता अभियान और भोजनालयों, पेंट्री कारों और बेस किचन का निरीक्षण भी किया जा रहा है। यात्रियों को प्लास्टिक कचरे को कम करने और कचरे का उचित निपटान केवल कूड़ेदानों में करने के लिए प्लास्टिक बोतल क्रशर मशीनों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हरित पहल के तहत, विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं।

स्वतंत्रता दिवस समारोह सप्ताह के दौरान स्वच्छता अभियान में पश्चिम रेलवे की सक्रिय भागीदारी स्वच्छता, स्थिरता और सार्वजनिक सहभागिता के प्रति इसकी निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

बजाज समूह के शिशिर बजाज को मिला वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित 'सर्वोत्तम नागरिक सम्मान'

मुंबई, 8 अगस्त। मुंबई के प्रतिष्ठित होटल सहारा स्टार में आयोजित एक भव्य समारोह में बजाज फाउंडेशन के चेयरमैन और बजाज समूह के वरिष्ठ मार्गदर्शक शिशिर बजाज को 'सर्वोत्तम नागरिक सम्मान -2025' से सम्मानित किया गया।

महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित इस सम्मान समारोह में महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति श्रीराम शिंदे तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार द्वारा अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ सम्मान मूर्तियों का सत्कार किया गया।सर्वोत्तम नागरिक सम्मान, मेघा श्रेय फाउंडेशन और श्रीमती सीमा सिंह द्वारा उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने समाज में अपने निःस्वार्थ समर्पण और सेवा के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में मिसाल कायम की है। इस वर्ष के समारोह में पद्मविभूषण डॉ. अनिल काकोडकर, पद्मभूषण डॉ. विजय भटकर, पद्मश्री डॉ. शंकर महादेवन, फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली, पद्मभूषण अनुपम खेर और पद्मश्री विजेंदर सिंह जैसे कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्व उपस्थित रहे। सम्मान प्राप्त करने के बाद श्री शिशिर बजाज ने कहा कि हमारे मूलभूत सामाजिक प्रयास 1926 से शुरू हुए, जब मेरे दादाजी श्री जमनालाल बजाज ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को समर्थन देने के लिए बजाज समूह की स्थापना की। उन्होंने बताया कि 1932 में उत्तर प्रदेश में हमारी पहली शुगर फैक्ट्री स्थापित की गई, जिसका उद्देश्य भारत को चीनी उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। तब से समूह ने व्यवसाय और सीएसआर दोनों क्षेत्रों में राष्ट्र निर्माण और भारतीय गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उत्कृष्ट कार्य किया है। उन्होंने कहा कि आज हम राजस्थान में मेरी जन्म स्थली सीकर जिले के 1000 गाँवों में और मेरे दादाजी की कर्मभूमि महाराष्ट्र के वर्धा जिले के 1000 से अधिक गाँवों में समाज कल्याण के कार्य कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य ग्रामीण भारत के प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का बहुमुखी विकास करना है, क्योंकि यह लक्ष्य 'विकसित और आत्मनिर्भर भारत' के उस निर्माण में अहम भूमिका निभाता है, जिसकी परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक के लिए निर्धारित की है।

देश के प्रमुख औद्योगिक समूहों में से एक बजाज समूह के परोपकारी संस्थान "बजाज फाउंडेशन" के चेयरमैन शिशिर बजाज वर्ष 2025 का "सर्वोत्तम नागरिक सम्मान" पुरस्कार ग्रहण करते हुए और मंच पर प्रतिष्ठित पुरस्कार के साथ दिखाई दे रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि बजाज फाउंडेशन, श्री शिशिर बजाज और उनके पुत्रों कुशाग्र बजाज एवं अपूर्व बजाज के नेतृत्व में ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। फाउंडेशन ने वर्धा, सीकर और ललितपुर जिलों के गाँवों में वर्षा जल संचयन, नदी पुनर्जीवन, सूक्ष्म सिंचाई, प्राकृतिक खेती, बागवानी, किसान पाठशालाएँ, महिला स्व-सहायता समूह, सौर पंप और बायोगैस संयंत्र जैसे नवीकरणीय ऊर्जा समाधान, किसान उत्पादक संगठन, और परिवर्तनकारी शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 6 लाख से अधिक परिवारों को सशक्त किया है, जिससे लगभग 22 लाख लोगों के जीवन में सुधार हुआ है। 'नेशन बिल्डिंग थ्रू बिजनेस एंड सर्विस' की विचारधारा के तहत, बजाज समूह भारत के सबसे सम्मानित और विविधीकृत औद्योगिक समूहों में से एक के रूप में स्थापित हुआ है। कुशाग्र बजाज के नेतृत्व में समूह की प्रमुख कम्पनियों में शामिल है, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड जो भारत की सबसे बड़ी एकीकृत चीनी कम्पनी है और उत्तर प्रदेश में 14 चीनी मिलों और 6 एथेनॉल संयंत्रों का संचालन करती है। एक अन्य कम्पनी बजाज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, उत्तर प्रदेश में 6 पावर प्लांटों का संचालन करती है, जिनमें 1,980 मेगावाट क्षमता वाला ललितपुर पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड का सुपर-क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन भी शामिल है, जो राज्य की लगभग 10% बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करता है। इसी प्रकार बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड अपने प्रमुख उत्पाद बजाज आमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल के साथ प्रीमियम हेयर ऑयल कैटेगरी में अग्रणी है। समाज सेवा और औद्योगिक उत्कृष्टता के अद्वितीय संगम के रूप में श्री शिशिर बजाज को मिला सर्वोत्तम नागरिक सम्मान पुरस्कार, उनके अभूतपूर्व योगदान की सच्ची पहचान है।

पश्चिम रेलवे द्वारा बांद्रा टर्मिनस एवं भगत की कोठी के बीच एक अतिरिक्त रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन

मुंबई,

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा त्योहारी सीजन रक्षाबंधन के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से बांद्रा टर्मिनस एवं भगत की कोठी स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर एक और स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार हैः

1. ट्रेन संख्या 04828/04827 बांद्रा टर्मिनस-भगत की कोठी स्पेशल [2 फेरे]

ट्रेन संख्या 04828 बांद्रा टर्मिनस-भगत की कोठी स्पेशल सोमवार, 11 अगस्त, 2025 को बांद्रा टर्मिनस से 10:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 04:30 बजे भगत की कोठी पहुँचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04827 भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल रविवार, 10 अगस्त, 2025 को भगत की कोठी से 14:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 07:25 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा, साबरमती, महेसाणा, पालनपुर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, जवाई बांध, फालना, रानी, मारवाड़, पाली मारवाड़ और लूनी स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2 टियर, एसी-3 टियर, एसी-3 टियर (इकोनॉमी), स्लीपर क्लास और द्वितीय श्रेणी के सामान्य डिब्बे होंगे।

ट्रेन संख्या 04828 की बुकिंग 09 अगस्त, 2025 से पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

वैश्विक आरोग्य पद्धति के अनुरूप है आयुष

(जीएनएस)।

आयुष मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी औषधियों के लिए फामाकोपिया मानकों को निर्धारित करने के लिए अपने अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी के लिए फामाकोपिया आयोग (पीसीआईएमएंडएच) की स्थापना की है, जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियम 1945 के अनुसार आधिकारिक सार-संग्रह के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा एमओए ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के साथ सहयोग किया और उत्पादों और सेवाओं के पारंपरिक एवं आधुनिक पहलुओं सहित भारतीय मानकों के निर्माण के लिए बीआईएस की आयुष प्रभाग परिषद के तहत प्रत्येक आयुष पद्धतियों (आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिग्पा और होम्योपैथी) के लिए सात अनुभागीय समितियों का गठन किया है। ये समितियां तकनीकी विशेषज्ञों, अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग प्रतिनिधियों और नियामक निकायों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर काम करती हैं, ताकि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप व्यापक, साक्ष्य-आधारित मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। बीआईएस ने कच्चे माल, विनिर्माण प्रक्रियाओं, पैकेजिंग और तैयार उत्पादों को कवर करते हुए भारतीय मानकों की एक श्रृंखला तैयार की है। अब तक आयुष प्रभाग परिषद के तहत सात अनुभागीय समितियों द्वारा उत्पादों और सेवाओं के पारंपरिक और आधुनिक पहलुओं सहित आयुष प्रणालियों से संबंधित 180 भारतीय मानक विकसित किए गए हैं। आयुष प्रणालियों पर तैयार किए गए मानक बीआईएस की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

भारत सरकार के सहयोग से विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने आयुर्वेद और यूनानी के प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए मानक दस्तावेज प्रकाशित किए हैं। इसके साथ ही आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध में डब्ल्यूएचओ की मानकीकृत शब्दावली भी जारी की गई है। इसके अलावा आयुष मंत्रालय ने दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक अंतरराष्ट्रीय हर्बल फामाकोपिया के विकास का सहयोग करने के लिए डब्ल्यूएचओ के साथ एक परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रालय आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी (एएसयू) दवाओं के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों के अनुसार औषधि उत्पाद प्रमाणन (सीओपीपी) को बढ़ावा देता है। पारंपरिक चिकित्सा में गुणवत्ता आश्वासन के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के अनुरूप एमओए के तहत भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फामाकोपिया आयोग (पीसीआईएम एंड एच) ने इंडोनेशिया गणराज्य के खाद्य और औषधि प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इन प्रयासों का उद्देश्य आयुष उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ाना है, जिससे अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप वैश्विक बाजारों में आयुष उत्पादों के प्रति उपभोक्ता विश्वास और स्वीकृति में सुधार हो सके।

आयुष मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव जाधव ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

हर घर तिरंगा अभियान 2025 के अंतर्गत पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन

"हर घर तिरंगा" अभियान 2025 के अंतर्गत पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में दिनांक 08.08.2025 (शुक्रवार) को भावनगर मंडल पर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में एक "तिरंगा प्रदर्शनी" का आयोजन किया गया था। भावनगर डिविजन के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार इस प्रदर्शनी का शुभारंभ मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा जी के कर कमल से एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री हिमाँशु शर्मा जी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। भावनगर मंडल के सभी अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया एवं प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय और महिला समिति संचालित किड्स हट तथा बाल मंदिर के बच्चों एवं अध्यापकों ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया एवं बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।

'हर घर तिरंगा' के इस अभियान के अंतर्गत भावनगर मंडल के मंडल कार्यालय के सभागृह में एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भावनगर परा के बच्चे एवं मंडल कार्यालय के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विविध ग्रुप को इस अवसर पर क्वीज कंपटीशन में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमांक वाले ग्रुप को प्रोत्साहित किया गया। इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री हुबलाल जगन जी की अध्यक्षता एवं उनके मार्गदर्शन में कार्मिक विभाग द्वारा आयोजित किया गया।

हर्बल दवाओं की सुरक्षा, विनियमन और प्रभावकारिता पर डब्ल्यूएचओ-आईआरसीएच कार्यशाला गाजियाबाद में संपन्न

(जीएनएस)।

आयुष मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सहयोग और भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी फामाकोपिया आयोग (पीसीआईएमएंडएच) के समर्थन से 6 से 8 अगस्त, 2025 के दौरान गाजियाबाद में तीन-दिवसीय डब्ल्यूएचओ-हर्बल दवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय नियामक सहयोग (आईआरसीएच) कार्यशाला का आयोजन किया।

इस कार्यशाला का उद्घाटन आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा और विश्व स्वास्थ्य संगठन-आईआरसीएच की अध्यक्ष डॉ. किम सुंगचोल ने आयुष मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन और पीसीआईएमएंडएच के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया। भूटान, ब्रुनेई, क्यूबा, घाना, इंडोनेशिया, जापान, नेपाल, पैराग्वे, पोलैंड, श्रीलंका और युगांडा के प्रतिनिधिमंडलों ने जहां इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, वहीं ब्राजील, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।

पश्चिम रेलवे पर रविवार, 10 अगस्त, 2025 को दिवसकालीन ब्लॉक नहीं

पश्चिम रेलवे के सांताक्रुज एवं माहिम स्टेशनों के बीच 09/10 अगस्त, 2025 की मध्यरात्रि को रात्रिकालीन ब्लॉक

मुंबई,

पश्चिम रेलवे पर रेलपथ, सिगनलिंग प्रणाली तथा ऊपरी उपस्करों के रख-रखाव हेतु शनिवार/रविवार की मध्यरात्रि अर्थात 09/10 अगस्त, 2025 को सांताक्रुज एवं माहिम स्टेशनों के बीच अप फास्ट लाइन पर 00.00 बजे से 04.00 बजे तक तथा डाउन फास्ट लाइन पर 00.30 बजे से 04.30 बजे तक जम्बो ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ब्लॉक अवधि के दौरान फास्ट लाइन की सभी ट्रेनें अंधेरी और चर्चगेट स्टेशनों के बीच धीमी लाइन पर चलाई जाएंगी।

तदनुसार, पश्चिम रेलवे के उपनगरीय खंड पर रविवार, 10 अगस्त, 2025 को कोई दिवसकालीन ब्लॉक नहीं रहेगा।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI

सम्पादकीय

भारत को दबाव में लाकर अपना हित साधने में लगा यूएस

भारत में मांसाहारी दुग्ध उत्पाद और चारा बेचना चाहता है अमेरिका दूध के बाजार को अमेरिका हड़पना चाहता है। जबकि वेंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वुछ माह पहले ही दस हजार नईं वृषि सहकारी समितियों को हरी झंडी दिखाईं है। अगले पांच साल में इनकी संख्या दो लाख तक पहुंचाने की है। इन्हीं सहकारी संस्थाओं के जरिए वृषि और दुग्ध उत्पादों को भारत से लेकर एशिया और यूरोप तक बाजार में पहुंचाने की है। भारत में मांसाहारी दुग्ध उत्पाद और चारा बेचना चाहता है अमेरिका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऊल-जलूल टैरिफ संबंधी घोषणाएं करके भारत पर बेवजह दबाव बनाने में लगे हैं। उन्होंने 1 अगस्त से भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का एकतरफा निर्णय ले लिया है। यही नहीं ट्रंप ने रूस से सैन्य उपकरण और कच्चा तेल खरीदने की वजह से अतिरित्त जुमार्ना लगाने की बात भी कही है। यह टैरिफ देशी भारतीय दुग्ध एवं वृषि उत्पाद हड़पने की दृष्टि से भी लगाया गया है। जिससे भारत दबाव में आकर इन उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोल दे। लेकिन भारत भलि-भांति जानता है कि अमेरिका के सस्ते अनाज,पसु चारा और मांसाहारी चीज (पनीर) के लिए भारतीय बाजार खोल दिया जाता है तो किसान तो तबाह होगा ही शाकाहारी संस्वृति को भी पलीता लगेगा। साथ ही भारत सरकार जिन प्राथमिक वृषि सहकारी समितियों (पैक्स) को बढ़ावा देकर वृषि और दूध उत्पादों को वैश्विक बाजार में लाने की पृष्ठभूमि तैयार कर रही है, वह विचार भी चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए सरकार ने साफ कह दिया है कि इन क्षेत्रों में बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। वैसे भी अब यह सच्चाईं सामने आ रही है कि एकतरफा वैश्वीकरण से दुनिया का भला होने वाला नहीं है। अतएव स्वदेशी उत्पादों के जरिए ही आत्मनिर्भर बने रहने की पहल जारी रखनी होगी। भारत इस दिशा में मजबूती से बढ़ भी रहा है। इसलिए ट्रंप जैसे वाचाल और सनकी शासक की परवाह करने की जरूरत नहीं है। भारत में गाय को माता यूं ही नहीं कहा जाता है। वे भारतीय त्रषि ही थे, जिन्होंने सबसे पहले जाना था कि गाय के दूध में ऐसे पोषक तत्व हैं, जो शरीर और दिमाग दोनों को ही स्वस्थ रखते हैं। यह दूध ही है, जिससे दही, मठा, मक्खन और घी जैसे सह-उत्पाद निकलते हैं। ये उत्पाद मिठाईं की दुकानों से लेकर डेयरी उद्योग के जरिए करोड़ों लोगों के रोजगार का मजबूत मध्ययम बने हुए हैं। लंबे समय तक गाय से पैदा बैल पर ही भारतीय वृषि निर्भर रही है। इसी वृषि की जीडीपी में 24 प्रतिशत की भागीदारी है। भारतीय दुग्ध उत्पादन से लेकर दूध पीने में दुनिया में पहले स्थान पर हैं। इसी दूध पर अमेरिकी बाजार के कब्जे के लिए अमेरिका अपने यहां उत्पादित मांसाहारी दुग्ध उत्पाद और पशु चारा बेचना चाहता है। अन्य यूरोपीय देशों की निगाह भी इस दूध के व्यापार पर भी टिकी हैं। इस बाबत अमेरिका और भारत के बीच 500 बिलियन डॉलर के व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। इसी समझौते की सूची में अमेरिकन मांसाहारी दूध के उत्पाद शामिल हैं। भारत सरकार ने इस बाबत दो टूक कह दिया है कि अमेरिकी दुग्ध उत्पादों और पशु चारे को भारतीय बाजार का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है। यह हमारे दुग्ध उत्पादक किसानों की आजीविका और उनकी संस्वृति की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा प्रश्न है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। दरअसल अमेरिका मांसयुत्त चीज (पनीर) और पनीर भारत में बेचने का इच्छुक है। इस चीज को बनाने की प्रव्रिया में बछड़े की आंत से बने एक पदार्थ का इस्तेमाल होता है। अत्यंत घिनौना वृत्य करके इसे चीज में मिलाया जाता है। शाकाहारी लोग इस प्रायिा को देख भी नहीं सकते हैं। इसलिए भारत के शाकाहारियों के लिए यह पनीर वंजित है। गौ-सेवक व गऊ को मां मानने वाला भारतीय समाज इसे स्वीकार नहीं करता। अमेरिका में गायों को मांसयुत्त चारा खिलाया जाता है, जिससे वे ज्यादा दूध दें। हमारे यहां गाय-भैंसें भले ही वूड़ेक चरे में मुंह मारती फिरती हों, लेकिन दुधारू पशुओं को मांस खिलाने की बात कोईं सपने में भी नहीं सोच सकता ? लिहाजा अमेरिका को चीज बेचने की इजाजत नहीं मिल पा रही है।

10 अगस्त, विश्व शेर दिवस : वन्यजीव संरक्षण में अग्रणी गुजरात

17 शेरों और 25 तेंदुओं की दहाड़ से गूंज रहा बरडा वन्यजीव अभयारण्य

गुजरात में एशियाई शेरों की आबादी 891 हुई, शेरों के आवास के विस्तार और संरक्षण का सफल मॉडल बना बरडा अभयारण्य

बरडा जंगल सफारी बनी पर्यटकों के लिए नया आकर्षण, इको-टूरिज्म को मिला बढ़ावा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'प्रोजेक्ट लायनश और इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के जरिए वन्यजीव संरक्षण में भारत की स्थिति हुई मजबूत

गांधीनगर, 08 अगस्त : भारत की शान एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास गुजरात में है, जो राज्य के लिए गर्व की बात है। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस के अवसर पर गिर के अलावा बरडा वन्यजीव अभयारण्य में एशियाई शेरों की मजबूत उपस्थिति का उल्लेख प्रासंगिक होगा, जो वन्यजीवों, विशेषकर शेरों के संरक्षण के लिए गुजरात की प्रतिबद्धता को दशार्ता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग ने बरडा अभयारण्य में वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग और सामुदायिक भागीदारी से शेरों के लिए अनुकूल आवास सुनिश्चित किया है। इसका सुखद परिणाम यह है कि बरडा अब 17 एशियाई शेरों का दूसरा घर बन गया है।

बरडा अभयारण्य में 17 एशियाई शेरों और 25 तेंदुओं की मौजूदगी

2023 की वन्यजीव गणना के अनुसार बरडा अभयारण्य में 17 एशियाई शेरों और 25 तेंदुओं की मौजूदगी है। वन एवं पर्यावरण विभाग ने घास के मैदानों की पुनर्स्थापना, शेरों के भोजन के लिए जानवरों की संख्या में वृद्धि तथा टेक्नोलॉजी-आधारित वन्यजीव ट्रैकिंग जैसे व्यापक संरक्षण उपाय किए हैं ताकि अभयारण्य अधिक से अधिक वन्यजीवों के लिए एक अनुकूल आवास बन सके। बरडा अभयारण्य की यह प्रगति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए 'प्रोजेक्ट लायन' के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसमें गिर के बाहर शेरों के आवास का विस्तार करना, वन्यजीवों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना शामिल है।

बरडा वन्यजीव अभयारण्य : वन्यजीव संरक्षण का एक रणनीतिक केंद्र

पोरबंदर के निकट स्थित बरडा वन्यजीव अभयारण्य आवास विविधीकरण के लिए 'प्रोजेक्ट लायन' के अंतर्गत एक मुख्य केंद्र है। बरडा वन्यजीव अभयारण्य अनिवार्य सुविधाओं और सुरक्षा के कारण शेरों के लिए एक आदर्श आवास बन गया है। यहां रेडियो कॉलर और रियल-टाइम ट्रैकिंग जैसे उपकरणों के माध्यम से शेरों की निगरानी और अधिक प्रभावी बन गई है। बरडा वन्यजीव अभयारण्य में शेरों और तेंदुओं, दोनों की मौजूदगी एक स्वस्थ इकोसिस्टम को दशार्ती है।

पर्यटकों के बीच बरडा जंगल सफारी का आकर्षण, इको-टूरिज्म को बढ़ावा

गुजरात वन विभाग इको-टूरिज्म को प्रोत्साहन देने और संरक्षण को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 16 अक्टूबर से 15 जून के दौरान बरडा वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी का आयोजन करता है। पर्यटकों को सफारी की एक ट्रिप (अधिकतम 6 लोग) के लिए कुल 2200 रुपए का खर्च करना होगा, जिसमें 1400 रुपए जिप्सी वाहन शुल्क, 400 रुपए गाइड शुल्क और सरकारी परमिट के लिए 400 रुपए का शुल्क शामिल हैं। इसके अलावा, पर्यटकों के लिए पार्किंग एरिया, वेटिंग लाउंज और सैनिटेशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस अभयारण्य में किलेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है, जो पूरे वर्ष पर्यटकों के लिए खुला रहता है।

वन्यजीव संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करके और लोगों को संरक्षण प्रयासों के केंद्र में रखकर वन्यजीव संरक्षण कर रहा है। स्थानीय समुदाय, विशेषकर मालधारी पशुपालक समूहों, इको-टूरिज्म और वन्यजीव संरक्षण में मदद करते हैं। यह सहभागी मॉडल केवल संरक्षण प्रयासों को ही मजबूत नहीं बनाता, बल्कि यह अभयारण्य की दीर्घकालिक सफलता में समुदायों की भागीदारी भी सुनिश्चित करता है।

गुजरात में शेरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि

2025 में हुई शेरों की गणना के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की आबादी 891 तक पहुंच गई है, जिनमें से 50 फीसदी से अधिक शेर गिर संरक्षित क्षेत्र के बाहर निवास करते हैं। यह परिवर्तन 'प्रोजेक्ट लायन' के अंतर्गत आवास विस्तार और समुदाय-संचालित संरक्षण की प्रभावशीलता पर जोर देता है। बरडा का विकास बड़े मांसाहारी जानवरों के संरक्षण में भारत के नेतृत्व को दशार्ता है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की वैश्विक पहल-इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) - शेर, बाघ, तेंदुआ और चीता जैसे मांसाहारी जानवरों के संरक्षण प्रयासों में भारत को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करती है।

एशियाई शेरों के संरक्षण में बरडा वन्यजीव अभयारण्य की उल्लेखनीय सफलता टिकाऊ विकास का एक शानदार उदाहरण है। यह मॉडल प्रधानमंत्री के विजन 'विकास भी, विरासत भी' के अनुरूप है, जो पर्यावरणीय विरासत के संरक्षण के साथ-साथ विकास भी सुनिश्चित करता है।

असम और त्रिपुरा के लिए विद्यमान केंद्रीय क्षेत्र विशेष विकास पैकेज (एसडीपी) योजना के अंतर्गत 4,250 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ चार नए घटकों को अनुमति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम और त्रिपुरा के लिए विद्यमान केंद्रीय क्षेत्र विशेष विकास पैकेज (एसडीपी) योजना के अंतर्गत 4,250 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ चार नए घटकों को अनुमति दी है।

विवरण:

● भारत सरकार और असम सरकार द्वारा असम के जनजातीय समूहों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओएस) के अनुसार असम के जनजाति बहुल गाँवों/क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये।

● भारत सरकार और असम सरकार द्वारा असम के दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (डीएनएलए)/दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल (डीपीएसी) समूहों के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार, असम के दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी/दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल के बसे हुए गाँवों/क्षेत्रों के उत्तरी कैचर हिल्स स्वायत्त परिषद (एनसीएचएसी) क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये।

● भारत सरकार और असम सरकार द्वारा असम के उल्फा समूहों के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार,

असम राज्य में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये।

● भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार द्वारा त्रिपुरा के नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) समूहों के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार, त्रिपुरा के जनजातियों के विकास के लिए 250 करोड़ रुपये।

वित्तीय पहलू: प्रस्तावित चार नए घटकों का कुल परिव्यय 7,250 करोड़ रुपये होगा, जिसमें से 4,250 करोड़ रुपये असम (4000 करोड़ रुपये) और त्रिपुरा (250 करोड़ रुपये) के लिए विशेष विकास पैकेजों की विद्यमान केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाएँगे, और शेष 3,000 करोड़ रुपये असम राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से प्रदान किए जाएँगे।

भारत सरकार, असम और त्रिपुरा की राज्य सरकारों और संबंधित राज्य के जातीय समूहों के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार, 4,250 करोड़ रुपये में से, वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक पाँच वर्षों की अवधि के लिए 4,000 करोड़ रुपये का परिव्यय असम के तीन घटकों के लिए और वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2028-29 तक चार वर्षों की अवधि के लिए 250 करोड़ रुपये का परिव्यय त्रिपुरा के एक घटक के लिए है।

रोजगार सृजन क्षमता सहित प्रभाव:

● बुनियादी ढाँचा और आजीविका परियोजनाएँ रोजगार सृजित करेंगी

● कौशल विकास, आय सृजन और स्थानीय उद्यमिता के माध्यम से युवाओं और महिलाओं को लाभान्वित करेंगी

● स्थिरता लाने और प्रभावित समुदायों के मुख्यधारा में सम्मिलित होने की उम्मीद है

लाभ: यह योजना विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों असम और त्रिपुरा के लिए लक्षित है। यह निम्नलिखित माध्यमों से भागीदारी को प्रोत्साहन देगी:

- विभिन्न मौजूदा सरकारी योजनाओं से पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं करने वाले कमजोर और वंचित लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार;

- युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों के माध्यम से रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहन देना, स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, शिक्षा, कौशल और आय को प्रोत्साहन देना;

- देश के अन्य भागों से पर्यटकों की संख्या बढ़ाना, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के अधिक अवसर सृजित होंगे। इसके माध्यम से, असम के जनजाति और दिमासा समुदायों, असम के विभिन्न अन्य ज़िलों में रहने वाले लोगों और त्रिपुरा के जनजाति समुदायों के लाखों लोग लाभान्वित होंगे। यह विशेष विकास पैकेजों की चल रही केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत एक नई पहल है। पिछले समझौता ज्ञापन -आधारित पैकेजों (जैसे, बोडो और कार्बी समूहों के लिए) ने शांति स्थापना और विकास में सकारात्मक परिणाम प्रदर्शित किए हैं।

पृष्ठभूमि: भारत सरकार, असम और त्रिपुरा राज्य सरकार और संबंधित जातीय समूहों (आदिवासी समूह - 2022, डीएनएलए/डीपीएससी - 2023, उल्फा - 2023, एनएलएफटी/एटीटीएफ - 2024) के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य बुनियादी ढाँचे और सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं के माध्यम से शांति, समावेशी विकास और पुनर्वास को प्रोत्साहन प्रदान करना है।

बहु-विषयक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार (मेरिट) स्कीम के लिए बजटीय सहायता को मंजूरी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 175 इंजीनियरिंग संस्थानों और 100 पॉलिटेक्निक संस्थानों सहित 275 तकनीकी संस्थानों में 'तकनीकी शिक्षा में बहु-विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान सुधार' (मेरिट) स्कीम के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनईपी-2020) के अनुरूप युक्तियों को क्रियान्वित कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और शासन में सुधार करना है।

यह एक 'केंद्रीय क्षेत्र स्कीम' है, जिसका कुल वित्तीय प्रभाव 2025-26 से 2029-30 की अवधि के लिए 4,200 करोड़ रुपये है। 4,200 करोड़ रुपये में से विश्व बैंक से ऋण के रूप में 2,100 करोड़ रुपये की बा' सहायता प्राप्त होगी।

लाभ:

इस स्कीम के अंतर्गत अनुमानित 275 सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थानों का चयन और सहायता की जाएगी। इनमें चुनिंदा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), राज्य इंजीनियरिंग संस्थान, पॉलिटेक्निक और संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय (एटीयू) शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, तकनीकी शिक्षा क्षेत्र से संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के विभागों को भी मेरिट योजना के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम से लगभग 7.5 लाख छात्र लाभान्वित होंगे।

रोजगार सृजन सहित प्रभाव:

इस योजना से अपेक्षित प्रमुख परिणाम/आउटपुट इस प्रकार हैं:

भाग लेने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में डिजिटलीकरण कार्यनीतियां,

तकनीकी पाठ्यक्रमों के बीच बहु-विषयक प्रोग्राम के लिए दिशानिदेर्शों का विकास,

छात्रों के अध्ययन और रोजगारपरक कौशल में वृद्धि,

छात्र समूहों में छात्रों की परिवर्तन दर में वृद्धि,

सुदृढ़ अनुसंधान और नवोन्मेषण वातावरण,

बेहतर गुणवत्ता आश्वासन और शासन तंत्र जिसके परिणामस्वरूप दीर्घकालिक लाभ होंगे,

प्रत्यायन में वृद्धि और बेहतर तकनीकी शिक्षा संस्थान-स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन,

प्रासंगिक, श्रम बाजार के अनुकूल पाठ्यक्रम और मिश्रित पाठ्यक्रम विकसित और लागू किए गए,

भावी शैक्षणिक प्रशासकों, विशेषकर महिला संकाय का विकास।

कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य

यह स्कीम सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों और पॉलिटेक्निकों में कार्यान्वित की जाएगी। ये युक्तियां एनईपी-2020 के अनुरूप हैं और इनका उद्देश्य भाग लेने वाले संस्थानों की गुणवत्ता, समानता और शासन को बढ़ाना है। इसे एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू किया जाएगा और इसमें एक केंद्रीय नोडल एजेंसी के माध्यम से केंद्र सरकार से भाग लेने वाली संस्थाओं को धन हस्तांतरण की सुविधा होगी।

आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान और एआईसीटीई, एनबीए आदि जैसे उच्च शिक्षा क्षेत्र में नियामकीय निकाय भी योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

रोजगार सृजन:

यह पहल एक व्यापक, बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से छात्रों की रोजगारपरकता में सुधार के लिए उनके कौशल को बढ़ाने पर जोर देती है। प्रमुख युक्तियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रस्तुत करना, उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम को अद्यतन करना, संकाय विकास कार्यक्रमों का आयोजन और अनुसंधान केंद्र स्थापित करना शामिल है।

विपणन कंपनियों को घरेलू एलपीजी में हुए नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में 30,000 करोड़ रुपए की मंजूरी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू रसोई गैस की बिक्री पर हुए घाटे के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तीन तेल विपणन कंपनियों (आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल) को 30,000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत की है। तेल विपणन कंपनियों को इस क्षतिपूर्ति राशि का वितरण पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। यह राशि बारह किस्तों में दी जाएगी।

उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी सिलेंडर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों अर्थात आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल द्वारा विनियमित कीमतों पर आपूर्ति किए जाते हैं।

एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 2024-25 के दौरान उच्च स्तर पर बनी रहीं और आगे भी ऊंची बनी रहेंगी। हालांकि, उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में उतार-चढ़ाव से राहत देने के लिए, बढ़ी हुई लागत का बोझ घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया जिससे तीनों तेल विपणन कंपनियों को भारी नुकसान हुआ। घाटे के बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने देश में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की है।

इस मुआवजे से तेल विपणन कंपनियों को कच्चे तेल और एलपीजी की खरीद, ऋण की अदायगी और अपने पूंजीगत व्यय को बनाए रखने जैसी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी जिससे देश भर में एलपीजी सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

यह कदम वैश्विक ऊर्जा बाजारों में उतार-चढ़ाव से उपभोक्ताओं की रक्षा करने और साथ ही इन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की वित्तीय स्थिति को बनाए रखने की सरकार की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। यह पहल, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत आने वाले घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं सहित सभी उपभोक्ताओं को स्वच्छ रसोई ईंधन की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

कैबिनेट ने 2157 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर तमिलनाडु में 4-लेन मरक्कनम-पुडुचेरी राजमार्ग (एनएच-332ए) के निर्माण को मंजूरी दी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने तमिलनाडु में मरक्कनम- पुडुचेरी (46 किलोमीटर) 4-लेन राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का विकास हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) के तहत किया जाएगा, जिसकी कुल पूंजीगत लागत 2,157 करोड़ रुपये होगी।

वर्तमान में, चेन्नई, पुडुचेरी, विलुप्पुरम और नागपट्टिनम के बीच संपर्क मौजूदा 2-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 332ए (एनएच-332ए) और संबंधित राज्य राजमार्गों पर निर्भर है, जहां यातायात की अधिकता के कारण, विशेष रूप से घनी आबादी वाले क्षेत्रों और गलियारे वाले प्रमुख कस्बों में, काफी भीड़भाड़ रहती है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, यह परियोजना मरक्कनम से पुडुचेरी तक लगभग 46 किलोमीटर लंबे एनएच-332ए को 4-लेन में अपग्रेड करेगी। इससे मौजूदा गलियारे पर भीड़भाड़ कम होगी, सुरक्षा में सुधार होगा और चेन्नई, पुडुचेरी, विलुप्पुरम और नागपट्टिनम जैसे तेजी से बढ़ते शहरों की आवागमन संबंधी जरूरतें पूरी होंगी।

यह परियोजना दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच-32, एनएच-332) और दो राज्य राजमार्गों (एसएच-136, एसएच-203) को जोड़ती है, जिससे तमिलनाडु के प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक केंद्रों तक निर्बाध संपर्क सुनिश्चित होता है। इसके अतिरिक्त, उन्नत गलियारा दो रेलवे स्टेशनों (पुडुचेरी, चिन्नाबाबूसमुद्रम), दो हवाई अड्डों (चेन्नई, पुडुचेरी) और एक छोटे बंदरगाह (कुड्डालोर) से जुड़कर मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन को बढ़ाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र में माल ढुलाई और यात्रियों की शीघ्र आवाजाही संभव होगी।

परियोजना के पूरा होने पर, मरक्कनम-पुडुचेरी खंड क्षेत्रीय आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, प्रमुख धार्मिक और आर्थिक केंद्रों के बीच संपर्क को मजबूत करेगा, पुडुचेरी में पर्यटन को बढ़ावा देगा और व्यापार एवं औद्योगिक विकास के नए रास्ते खोलेगा। यह परियोजना लगभग 8 लाख मानव-दिवस प्रत्यक्ष और 10 लाख मानव-दिवस अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा करेगी, और आसपास के क्षेत्रों में विकास, प्रगति और समृद्धि के नए रास्ते खोलेगी।

जीते जी सुख भोगिए, मरते करिए दान

कुछ ऐसा कर जाइए ,जिससे जीवन बने महान- अंकिता अवस्थी

अंगदान महादान (उपहार ज़िन्दगी का)

मनुष्य जीवन अनमोल है, परंतु कुछ परिस्थितियों में लोगों की जान केवल इस कारण नहीं बच पाती कि उन्हें समय पर आवश्यक अंग नहीं मिलते। ऐसे में अंगदान (ड१ॅल्ल ऊ्नल्लं३्नल्ल) एक ऐसा महान कार्य है, जो किसी के जीवन की डोर फिर से जोड़ सकता है। यह न केवल एक व्यक्ति के जीवन को बचाता है, बल्कि समाज को एक नई दिशा भी देता है।

अंगदान क्या है?

अंगदान का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपने शरीर के एक या अधिक अंगों को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना।

यह दान व्यक्ति के जीवित रहते भी हो सकता है (जैसे—एक किडनी, लिवर का हिस्सा) या मृत्यु के पश्चात (जैसे—हृदय, फेफड़े, नेत्र, त्वचा आदि)।

क्यों जरूरी है अंगदान?

भारत समेत पूरी दुनिया में लाखों लोग अंग विफलता से जूझ रहे हैं। इनमें से कई लोग समय पर अंग न मिलने के कारण असमय मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यदि अधिक लोग अंगदान के लिए आगे आएं, तो न जाने कितने जीवन बचाए जा सकते हैं।

रक्षाबंधन, भाई-बहन के अटूट प्रेम का अनमोल उत्सव

योगी सरकार का ऐलान, रक्षाबंधन पर बहनों के लिए मुफ्त बस यात्रा

(जीएनएस)।

रक्षाबंधन, एक ऐसा पवित्र पर्व जो न केवल एक धागे की गांठ है, बल्कि दिलों को जोड़ने वाला, प्रेम और विश्वास का अनमोल बंधन है। यह त्योहार भाई-बहन के रिश्ते की गहराई को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है, जहां स्नेह की डोर, विश्वास की नींव और सुरक्षा का वचन एक-दूसरे को बांधे रखते हैं। 'रक्षा' का अर्थ है सुरक्षा और 'बंधन' है वह गांठ जो इस रिश्ते को अटूट बनाती है। श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पर्व भारत की सांस्कृतिक धरोहर का एक चमकता सितारा है, जो हर दिल को छू लेता है।

आध्यात्मिक और ऐतिहासिक आलम रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक भावना है जो प्रेम, त्याग और समर्पण की कहानियों से सजी है। इसकी जड़ें पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में गहरे तक समाई हैं, जो हमें रिश्तों की महत्ता सिखाती हैं।

द्रौपदी और कृष्ण की अमर कथा, जब भगवान कृष्ण की उंगली से खून बहने लगा, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। यह छोटा-सा कार्य प्रेम और निःस्वार्थ भाव का प्रतीक था। कृष्ण ने इस स्नेह का मान रखते हुए द्रौपदी को हर संकट में रक्षा करने का वचन दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि राखी का धागा केवल सूत का नहीं, बल्कि दिल से दिल तक पहुंचने वाला एक विश्वास है।

रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी, जब चित्तौड़ की रानी कर्णावती पर संकट आया, उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर भाई के रूप में सहायता मांगी। हुमायूं ने इस बंधन का सम्मान करते हुए उनकी रक्षा के लिए कदम बढ़ाया। यह कहानी राखी के उस बंधन को दशार्ती है जो रक्त के रिश्तों से परे जाकर मानवता को जोड़ता है।

यम और यमुना का पवित्र बंधन, यमराज और उनकी बहन यमुना की कथा भी रक्षाबंधन की नींव को और मजबूत करती है। यमुना ने अपने भाई यमराज की कलाई पर राखी बांधी और उनके सुख-समृद्धि की कामना की। यमराज ने वरदान दिया कि जो भाई अपनी बहन से राखी बंधवाएगा, उसे दीघार्यु और सुरक्षा प्राप्त होगी। यह कथा हमें सिखाती है कि रक्षाबंधन का बंधन मृत्यु को भी प्रेम के आगे झुका सकता है।

रक्षाबंधन का दिन केवल एक रस्म नहीं, बल्कि खुशियों का मेला है। सुबह से ही घरों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ती है। बहनें रंग-बिरंगी राखियों, मिठाइयों और थाल सजाकर अपने भाई की कलाई पर प्रेम की डोर बांधती हैं। भाई अपनी बहन को उपहार, आशीर्वाद और जीवन भर रक्षा का वचन देते हैं। यह पल न केवल रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि परिवार को एकजुट कर हंसी-खुशी का माहौल बनाता है। मिठाइयों की मिठास, राखी की चमक, और भाई-बहन के बीच की हंसी-मजाक इस दिन को अविस्मरणीय बनाते हैं। आजकल तो राखी केवल भाई-बहन तक सीमित नहीं रही, दोस्त, पड़ोसी और शुभचिंतक भी इस बंधन में शामिल होकर प्रेम और सम्मान का आदान-प्रदान करते हैं।

रंग आज के दौर में रक्षाबंधन ने नए रंग अपनाए हैं। ऑनलाइन राखियां, वीडियो कॉल पर राखी बांधने की रस्म, और डिजिटल उपहारों ने इस त्योहार को वैश्विक बना दिया है। भले ही मीलों की दूरी हो, लेकिन राखी का धागा दिलों को जोड़े रखता है। कुछ क्षेत्रों में रक्षाबंधन को सामाजिक एकता के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है, जहां लोग अपने समुदाय के लिए एक-दूसरे को राखी बांधकर भाईचारे का संदेश देते हैं।

रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि एक वादा है, प्रेम का, विश्वास का और एक-दूसरे के लिए हर कदम पर खड़े रहने का। यह हमें सिखाता है कि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं, जब उनमें निःस्वार्थ भाव, सम्मान और देखभाल हो। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि चाहे कितने भी तूफान आएं, भाई-बहन का बंधन हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़ा रहता है।

रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो हर दिल में बस जाता है। यह वह लम्हा है जब बहन की दुआएं भाई की ढाल बनती हैं, और भाई का वचन बहन की ताकत। तो आइए, इस रक्षाबंधन पर अपने रिश्तों को और मजबूत करें, प्रेम की डोर को और गहरी करें, और इस पवित्र बंधन को पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाएं।

रक्षाबंधन पर योगी सरकार का तोहफा, बहनों को 3 दिन मुफ्त बस यात्रा,

इस साल रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को खास सौगात दी है। 8 अगस्त 2025 की सुबह 6 बजे से 10 अगस्त 2025 की रात 12 बजे तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (वढरफ्लउ) की बसों में बहनें मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। यह पहल रिश्तों को जोड़ने और पर्व के उत्साह को बढ़ाने का सराहनीय कदम है।

उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को सुदृढ़ करने के उपायों पर प्रकाश डाला गया

बदलाव के लिए सहयोग को लेकर आयोजित हुई राउंडटेबल बैठक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक बाल शिक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। लखनऊ में एक उच्च स्तरीय राउंडटेबल बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा, सेसमी वर्कशॉप इंडिया ट्रस्ट और मैरिको लिमिटेड शामिल हुए। इस कार्यक्रम का नाम था - "अर्ली फाउंडेशन्स, ब्राइट फ्यूचर्स"। इसमें सरकार,सीएसआर, शिक्षा जगत और समाजिक संस्थाओं से जुड़े 80 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। सभी ने मिलकर राज्य में बच्चों के लिए आनंददायक, समावेशी और व्यापक प्रारंभिक शिक्षा मॉडल पर चर्चा की।

बैठक का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2022 के विचारों को आगे बढ़ाना था। इसमें खास ध्यान आंगनबाड़ी केंद्रों को खेल, सहयोग और उद्देश्य के माध्यम से बेहतर बनाना रहा।

श्रीमती लीना जौहरी, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास, उत्तर प्रदेश ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्री-स्कूल शिक्षा एक नया विषय है। ऐसे संवाद बहुत जरूरी हैं, ताकि व्यवहारिक व प्रभावी रणनीतियां बन सकें। उन्होंने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर यानि ढांचा जरूरी है, लेकिन असली बदलाव तो तभी आएगा जब हम बच्चों के लिए जिज्ञासा जगाने वाला, माता-पिता को भरोसेमंद लगने वाला और अनुकूल वातावरण तैयार करें।

मैरिको लिमिटेड की प्रमुख शिक्षा पहल "निहार शांति पाठशाला फनवाला" के माध्यम से 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए "लर्न, प्ले, ग्रो' कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम सेसमी वर्कशॉप इंडिया के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। अब अपने दूसरे वर्ष में यह कार्यक्रम 60 से बढ़ाकर 100 आंगनवाड़ी केंद्रों में पहुँच चुका है। यह कार्यक्रम बहराइच जिले में 1500 बच्चों और उनके माता-पिता तक पहुँच चुका है। इसमें खेल के माध्यम से सीखने और स्कूल के लिए तैयारी पर जोर दिया जा रहा है। मैरिको के निरंतर सहयोग और सेसमी वर्कशॉप इंडिया के बेहतरीन प्रयास से उच्च गुणवत्तापूर्ण कार्य संपन्न हुए हैं। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकताओं की क्षमता निर्माण और उत्साहजनक शैक्षणिक वातावरण बना है। इस प्रकार, आजीवन शिक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार हुआ है और भारत के प्रारंभिक शिक्षा लक्ष्यों में सार्थक योगदान दिया है।

मैरिको के मुख्य विधिक अधिकारी और सीएसआर कमेटी के सचिव अमित भसीन ने कहा कि हम मानते हैं कि किसी भी बिजनेस की असली सफलता समाज के लिए किए गए योगदान से मापी जाती है। शिक्षा हमारी प्राथमिकता है। निहार शांति पाठशाला फनवाला के जरिए हम हर बच्चे को आगे बढ़ने का अवसर देना चाहते हैं। उन्होंने सेसमी वर्कशॉप इंडिया को उनके साथ साझेदारी के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि यह यात्रा केवल आँकड़ों की नहीं, बल्कि बदलाव की है। सेसमी वर्कशॉप इंडिया ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी, सोनाली खान ने भी कहा कि हर बच्चे को सीखने और आगे बढ़ने का हक है। जब सरकार, संस्थाएं और कंपनियां मिलकर काम करती हैं, तभी असली बदलाव होता है।

इस बैठक में कई प्रमुख संगठनों ने भाग लिया। इसमें एचसीएल फाउंडेशन, जपाईगो, रूम टू रीड, प्रथम, आगा खान फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, सेन्ट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, अर्न्स्ट एंड यंग और टाटा ट्रस्ट हैं। बैठक में शामिल सभी ने अपने अनुभव साझा किए और बच्चों की शिक्षा के लिए साझा जिम्मेदारी पर जोर दिया।

अनेक बहनों को मिला जीवन ज्योति रक्षा सम्मान

जौनपुर भाई-बहन के प्रेम और विश्वास के पर्व रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर आज जीवन ज्योति सेवा फाउण्डेशन द्वारा रामनगर, ब्लॉक सुईथाकला, शाहगंज, जौनपुर में आयोजित सम्मान समारोह में अनेक बहनें जीवन ज्योति रक्षा सम्मान से सम्मानित हुईं।

समारोह में जीवन ज्योति सेवा फाउंडेशन के उपाध्यक्ष जितेन्द्र कुमार सिंह को रामनगर, ब्लॉक सुईथाकला, शाहगंज, जौनपुर की 500 से अधिक बहनों ने प्रेम और विश्वास के प्रतीक रक्षा सूत्र को बांध कर अपना असीम स्नेह और आशीर्वाद दिया।

कार्यक्रम में जितेन्द्र कुमार सिंह ने क्षेत्र की अनेक बहनों को पुष्प गुच्छ, अंग वस्त्र, मिष्ठान और स्मृति चिन्ह भेंट कर जीवन ज्योति रक्षा सम्मान से सम्मानित किया। अपने संबोधन में श्री सिंह ने कहा कि क्षेत्र की बहनों ने आज रक्षा सूत्र बांध कर जो स्नेह प्रदान किया है, उसका मैं सदैव ऋणी और उनकी सभी समस्याओं के लिए तत्पर रहूंगा। इस अवसर पर ज्योति सिंह अध्यक्ष जीवन ज्योति सेवा फाउंडेशन, राकेश वर्मा जिला उपाध्यक्ष भाजपा जौनपुर, अवधेश दुबे अर्शिया मंडल अध्यक्ष भाजपा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

मेरे खून का एक एक कतरा हिंदू बहन-बेटियों के सुरक्षा के लिए समर्पित : गोपाल राय

रक्षा बंधन पर गोपाल राय को 51 बहनों ने बांधी राखी,उनके सनातन संघर्षों का किया सम्मान

लखनऊ, रक्षा बंधन के पावन अवसर पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय को देशभर से आई 51 हिंदू बहनों ने राखी बांधकर सम्मानित किया। यह आयोजन मात्र एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि उन बहनों की सामूहिक कृतज्ञता और विश्वास का प्रतीक बना, जिन्होंने गोपाल राय को नारी सुरक्षा, धर्म रक्षण और सांस्कृतिक चेतना के सशक्त प्रहरी के रूप में स्वीकार किया है। बहनों ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि यह राखी केवल एक धागा नहीं, बल्कि एक संकल्प है — उन हाथों की रक्षा का, जिन्होंने नारी सम्मान की पुनर्स्थापना के लिए अथक संघर्ष किया है। यह दृश्य भावनात्मक भी था और लोगों के बीच गोपाल राय के कार्यों के प्रति बढ़ते सम्मान को दशार्ता था, जहां उन्हें एक सामाजिक और

धार्मिक नेतृत्वकर्ता के रूप में देखा गया।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने गोपाल राय के उन कार्यों की सराहना की, जिनकी गूंज अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुनाई देने लगी है। उन्होंने लव जिहाद से पीड़ित सैकड़ों हिंदू बहनों की घर वापसी करवाई और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर दिया। छांगुर जैसे जिहादी तत्वों के चंगुल से सैकड़ों हिंदू परिवारों को मुक्त कराकर उन्होंने उन्हें भयमुक्त जीवन की ओर अग्रसर किया। देशद्रोही छांगुर को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका रही। धमकियों और दबावों के बावजूद उन्होंने कभी झुकने का नाम नहीं लिया और पूरी मजबूती के साथ सनातन धर्म की रक्षा में डटे रहे।

गोपाल राय ने 'सनातन हेल्पलाइन सेवा' की शुरूआत कर संकट में फंसे सनातनियों को तत्काल सहायता उपलब्ध करवाई। उन्होंने धर्मांतरण के विरुद्ध खुला मोर्चा लेते हुए हजारों लोगों को पुनः सनातन धर्म की ओर लौटाया। युवाओं को जागरूक कर उन्हें संगठित किया और उनके भीतर अपने धर्म, संस्कृति और अस्तित्व के प्रति चेतना जागृत की। लखनऊ से मुर्शिदाबाद तक निकाली गई 'सनातन आक्रोश यात्रा' के माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया कि अब अन्याय के विरुद्ध हर सनातनी एकजुट होकर खड़ा होगा।

अयोध्या जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न

अयोध्या। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की जुलाई माह की बैठक (छमाही) कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हई, जिसमें विभिन्न 20 विद्यालयो के प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया।

बैठक में उपस्थित के बारे में अवगत कराया गया तथा को अद्यतन वैध कराने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया। बैठक में उपस्थित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि विद्यालय यानो के समस्त प्रपत्र वैध कराये जाये। ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध जिनके विद्यालय यानों का प्रपत्र ठीक नही कराया जा रहा है, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा समस्त स्कूल के प्रतिनिधियो को वाहनो के प्रपत्र वैध रखने तथा विद्यार्थियो की सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय करने हेतु निर्देश भी दिया गया

बैठक में उपस्थित एआरटीओ प्रशासन / प्रवर्तन डॉ० आर० पी० सिंह द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को परमिट समाप्त, फिटनेस समाप्त विद्यालय वाहनो की सूची उपलब्ध कराते हुए ऐसे विद्यालयो को अपने स्तर से भी निर्देश देने हेतु आग्रह किया गया। बैठक में एआरटीओ द्वारा स्कूल वाहनों के विरुद्ध जुलाई में चलाये गये अभियान को बताते हुए कार्य का विवरण भी प्रस्तुत किया गया तथा अवगत कराया गया कि विशेष अभियान में मानक के अनुरुप न पाये जाने वाले 64 स्कूल वाहनो का चालान करते हुए 17 वाहनो को बन्द किया गया जिसमे 10 वाहन बिना फिटनेस के थे।

जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को विद्यालयो में त्रैमासिक बैठक सुनिश्चित कराने तथा बैठक में सम्बन्धित सदस्यो की सहभागिता एवं वाहनो के प्रपत्र वैध कराने हेतु कड़े निर्देश दिये गये।

बैठक में उपस्थित सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन अयोध्या ऋतु सिंह द्वारा वाहनो के परमिट प्राप्त करने तथा चालको के चरित्र सत्यापन एवं विद्यालय यान में बालिका विद्यार्थी होने पर महिला परिचारिका की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु विद्यालय प्रबन्धन को निर्देश दिये गये। इसके अलावा यह भी बताया गया कि जनपद अयोध्या में स्कूली वाहनों के रुप में अद्यतन पंजीकृत 25 स्कूली वाहनों ने अभी तक परमिट प्राप्त नही किया है, जिसकी सूची पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग एवं प्रवर्तन अधिकारियो को दे दी गयी है ताकि उन पर कठोर कार्यवाही की जाय। बाकी ऐसे स्कूली वाहन जिसकी परमिट समाप्त हो चुकी है उन सभी को नोटिस प्रेषित की जा चुकी है, यदि उनके द्वारा शीघ्र परमिट नवीनीकरण नही कराया जाता तो उनके विरुद्ध सुसंगत नियमो के आलोक में कार्यवाही की जायेगी।आरटीओ अयोध्या ऋतु सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों को लाने ले जाने में एक घंटे से अधिक का समय ना लगे यह सुनिश्चित किया जाये । स्कूल परमिट आवेदन के समय निजी ठेका गाड़ी संचालक द्वारा विद्यालय /अभिभावकों के साथ करार पत्र भी स्कूल के संस्तुति के साथ उपलब्ध करना आवश्यक है।

बैठक में उपस्थित अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री ए.पी. सिंह द्वारा विद्यालय प्रबन्धन को यथा आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु कहा गया।जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की जुलाई माह की बैठक (छमाही) कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हई, जिसमें विभिन्न 20 विद्यालयो के प्रतिनिधि प्रतिभाग किए। बैठक में उपस्थित के बारे में अवगत कराया गया तथा को अद्यतन वैध कराने हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया। बैठक में उपस्थित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि विद्यालय यानो के समस्त प्रपत्र वैध कराये जाये। ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध जिनके विद्यालय यानों का प्रपत्र ठीक नही कराया जा रहा है उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा समस्त स्कूल के प्रतिनिधियो को वाहनो के प्रपत्र वैध रखने तथा विद्यार्थियो की सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय करने हेतु निर्देश भी दिया गया

बैठक में उपस्थित एआरटीओ प्रशासन / प्रवर्तन डॉ० आर० पी० सिंह द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को परमिट समाप्त, फिटनेस समाप्त विद्यालय वाहनो की सूची उपलब्ध कराते हुए ऐसे विद्यालयो को अपने स्तर से भी निर्देश देने हेतु आग्रह किया गया। बैठक में एआरटीओ द्वारा स्कूल वाहनों के विरुद्ध जुलाई में चलाये गये अभियान को बताते हुए कार्य का विवरण भी प्रस्तुत किया गया तथा अवगत कराया गया कि विशेष अभियान में मानक के अनुरुप न पाये जाने वाले 64 स्कूल वाहनो का चालान करते हुए 17 वाहनो को बन्द किया गया जिसमे 10 वाहन बिना फिटनेस के थे।

बैठक में उपस्थित सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन अयोध्या ऋतु सिंह द्वारा वाहनो के परमिट प्राप्त करने तथा चालको के चरित्र सत्यापन एवं विद्यालय यान में बालिका विद्यार्थी होने पर महिला परिचारिका की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु विद्यालय प्रबन्धन को निर्देश दिये गये। इसके अलावा यह भी बताया गया कि जनपद अयोध्या में स्कूली वाहनों के रुप में अद्यतन पंजीकृत 25 स्कूली वाहनों ने अभी तक परमिट प्राप्त नही किया है, जिसकी सूची पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग एवं प्रवर्तन अधिकारियो को दे दी गयी है ताकि उन पर कठोर कार्यवाही की जाय। बाकी ऐसे स्कूली वाहन जिसकी परमिट समाप्त हो चुकी है उन सभी को नोटिस प्रेषित की जा चुकी है, यदि उनके द्वारा शीघ्र परमिट नवीनीकरण नही कराया जाता तो उनके विरुद्ध सुसंगत नियमो के आलोक में कार्यवाही की जायेगी।आरटीओ अयोध्या ऋतु सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों को लाने ले जाने में एक घंटे से अधिक का समय ना लगे यह सुनिश्चित किया जाये । स्कूल परमिट आवेदन के समय निजी ठेका गाड़ी संचालक द्वारा विद्यालय /अभिभावकों के साथ करार पत्र भी स्कूल के संस्तुति के साथ उपलब्ध करना आवश्यक है।

बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को विद्यालयो में त्रैमासिक बैठक सुनिश्चित कराने तथा बैठक में सम्बन्धित सदस्यो की सहभागिता एवं वाहनो के प्रपत्र वैध कराने हेतु कड़े निर्देश दिये गये। बैठक में उपस्थित अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री ए.पी. सिंह द्वारा विद्यालय प्रबन्धन को यथा आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु कहा गया। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक प्रतिनिधि डॉ० बसन्त कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अवनीश पाण्डेय अन्य सहित प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) ए.पी. सिंह द्वारा धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक समाप्त की गयी।

कंटेनर को बचाने में गहरी खाई में पलटी बस, 44 यात्रियों की बची जान

(जीएनएस)। / शारिक जैदी

बिजनौर।

धामपुर में शेरकोट नेशनल हाइवे-74 पर शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा टल गया, जब 44 यात्रियों से भरी रूपेडिहा डिपो की रोडवेज बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गई। गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी की जान नहीं गई।

बस चालक रामनिवास के अनुसार, रूपेडिहा से हरिद्वार जा रही बस राजपूताना के पास पहुंची ही थी कि अचानक सामने से एक तेज रफ्तार कंटेनर आ गया। टक्कर से बचने के लिए उन्होंने बस को कच्चे रास्ते की ओर मोड़ा, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया।

हादसे के बाद बस में चीख-पुकार मच गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। क्रेन की मदद से बस को सीधा किया गया। चार यात्रियों को हल्की चोटें आईं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार देकर घर भेज दिया गया।

पुलिस क्षेत्राधिकारी अभय कुमार पांडे ने बताया कि समय रहते बचाव कार्य शुरू होने से बड़ी जनहानि टल गई। पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद यात्रियों और पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली।

इंसाफ के सिपाहियों का सम्मान, समाज सेवा का अनमोल पैगाम, अधिवक्ताओं का सम्मान, समाज सेवा का पैगाम

लखनऊ, नवाबों की नगरी, जहाँ तहजीब और संस्कृति की मिठास बसी है, वहाँ एक बार फिर इंसाफ और समाज सेवा की खुशबू फैली। चौक क्षेत्र के बिल्लौचपुरा स्थित रॉयल पैलेस के भव्य सभागार में, ऑल इंडिया जामियतुल कुरैश द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिवक्ता परिषद सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। यह आयोजन न केवल अधिवक्ताओं के अथक परिश्रम को सलाम था, बल्कि समाज में इंसाफ और भाईचारे की मशाल जलाने का एक सुनहरा अवसर भी बना। यहाँ हर दिल में एक ही गूंज थी, सच्चाई, मेहनत और समाज सेवा का सम्मान!

जब बात इंसाफ की हो, तो अधिवक्ता समाज के वो सिपाही हैं, जो कमजोरों की आवाज बनकर उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं। इस समारोह में लखनऊ के तमाम अधिवक्ताओं को उनके इस समर्पण के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि, ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, जिनकी सादगी और विद्वता हर दिल को छूती है, ने अपने करकमलों से अधिवक्ताओं को फूलों का हार पहनाया। यह हार केवल फूलों का नहीं, बल्कि सम्मान, विश्वास और समाज के प्रति उनके योगदान का प्रतीक था। मौलाना खालिद रशीद ने अपने उद्बोधन में कहा, इंसाफ का रास्ता कठिन हो सकता है, पर यही वह राह है जो

समाज को एकता और समृद्धि की ओर ले जाती है। उनके शब्दों ने सभागार में उपस्थित हर शख्स के दिल में जोश और प्रेरणा का संचार किया।

इस अवसर पर मंच की शोभा बढ़ाने वालों में कई गणमान्य व्यक्तित्व शामिल थे। एडवोकेट वसीम सिद्दीकी, जिनके कानूनी क्षेत्र में योगदान को हर कोई सलाम करता है, शहाबुद्दीन कुरैशी, ऑल इंडिया जामियतुल कुरैश के राष्ट्रीय सचिव, जिनका सामाजिक कार्य प्रेरणा का स्रोत है; समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री यामीन खान, जिनकी समाज सेवा की गाथा लखनऊ की गलियों में गूंजती है, हाजी रहनुमा कुरैशी, हाजी पप्पू कुरैशी, शाबू और सईद उज्मा जैसे समाज के सजग प्रहरी, इन सभी ने मिलकर इस आयोजन को एक अविस्मरणीय उत्सव बनाया। इनके एकजुट प्रयासों ने यह साबित किया कि जब समाज के लोग एक साथ आते हैं, तो सच्चाई और इंसाफ का परचम लहराता है।

यह समारोह केवल एक आयोजन नहीं था, बल्कि समाज सेवा और इंसाफ की राह पर चलने वालों के लिए एक प्रेरणा का मंच था। अधिवक्ता, जो दिन-रात कानून की किताबों में डूबकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए लड़ते हैं, उनके इस समर्पण को सम्मानित करना हर किसी के लिए गर्व का क्षण था। यह आयोजन इस बात का प्रतीक बना कि समाज में बदलाव लाने के लिए जरूरी है एकता, साहस और सच्चाई का जज्बा। हर सम्मानित अधिवक्ता के चेहरे पर गर्व की चमक और समाज के प्रति और अधिक सेवा करने का संकल्प साफ झलक रहा था।

लखनऊ, जो अपनी गंगा-जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, एक बार फिर इस आयोजन के माध्यम से अपनी उदारता और एकता का परिचय दे गया। यहाँ हर धर्म, हर वर्ग के लोग एक मंच पर जुटे, और एक ही संदेश गूंजा, इंसाफ और समाज सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। अधिवक्ताओं के इस सम्मान ने यह दिखाया कि कानून की ताकत केवल कागजों तक सीमित नहीं, बल्कि यह समाज के हर उस शख्स तक पहुंचती है, जो हक और सच्चाई की उम्मीद में जीता है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिवक्ता परिषद का यह सम्मान समारोह लखनऊ के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह आयोजन न केवल अधिवक्ताओं के लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बना, जो समाज में बदलाव लाना चाहता है। यह समारोह एक संदेश दे गया। सच्चाई की राह पर चलने वाले कभी अकेले नहीं होते।